सोसायटी फोर सस्टेनेबल डिवलपमेन्ट,
करौली, (राजस्थान)–322 241
फोन : (07464) 21065

वार्षिक रिपोर्ट – 1995–96

सोसायटी फोर सस्टेनेबल डिवलपमेन्ट (संस्थान) का यह वर्ष नई संभावनाओं के साथ सोच को क्रियान्वित करने तथा भविष्यकी रूपरेखा तय करने वाला रहा । इस वर्ष मे संस्था मे नये परिवर्तन हुए तथा संस्थाने अपने कार्य का मिशन तथा लक्ष्य तय किया ।

संस्था ने अपने मिशन के रूप में "सतत विकास व प्राकृतिक संसाधनो के प्रबंध मे लोगों की भागीदारी को बढावा" देने का निश्चय किया । इसके लिए शिक्षण, संचार व सूचना के साथ आदर्श प्रतिरूप विकसित करने की प्रक्रिया को माध्यम बनाया गया । संस्था ने अपने कार्य क्षेत्र में सवाईमाधोपुर जिले की करोली व सपोटरा पंचायत समितियों को निर्धारित किया । शुरूआत में इस वर्ष कैलादेवी बन्यजीव अभ्यारण्य के अन्दर व उसके आस पास के गाँवो में अपनी गतिविधियां शुरू की ।

प्राकृतिक संसाधनो का प्रबंध

1. वनों के प्रबंध में लोगों की भागीदारी

इस क्षेत्र के लोगों के जीवनयापन का मूल साधन पशुपालन है । वन क्षेत्र के आसपास के लोग जंगल में पशुओं को चराकर अपना लालनपालन करते हैं । कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के बनने व इसे प्रबंध के लिए रणथम्भोर बाघ परियोजना के अंतर्गत लिए जाने के बाद अभ्यारण्य के अन्दर बसे लोगों मे शुरू में वहाँ से हटाये जाने के भय व नियमो के कडा कर देने से प्राकृतिक वनो व वन्य जीवो के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ तथा उन्होने जंगलो को भारी नुक्सान पहुँचाया । वन विभाग द्वारा लोगों को जबरदस्ती नही हटाने तथा उन्हे जंगल से आवश्यक सभी सुविधायें व लाभ उपलब्ध होते रहने कि वजहसे लोगों ने गाँवों में वन सुरक्षा पंचायत कर जंगल को नुक्सान नही पहुंचाने तथा जंगल बचाव के अपने नियम बनाये । यह प्रक्रिया अभ्यारण्य के कई गाँवो में शुरू हुई जो बाद में कुछ कारणो से रुक गई ।

संस्था वन विभाग व ग्रामीणो के मध्यस्थ का कार्य कर रही है । संस्था द्वारा अब अभ्यारण्य की सीमा के अंदर के सभी गाँवो में इस प्रक्रिया को वापस शुरू करने तथा इसमे आने वाली अडचनो को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । संस्था द्वारा कई गाँवो में वन विभाग व ग्रामीणों के मध्य मिल बैठकर इस प्रक्रिया को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे अभ्यारण्य के बाहर के गाँवो पर भी प्रभाव पडने की आशा है । कई गाँवो में ग्रामीणों की मदद से वन क्षेत्र को संरक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है । ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी स्थानीय प्रशासनिक व वन अधिकारीयों तथा नीति निर्माताओं को देने का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है । ग्रामीणों के उत्साह वर्धन के लिए मीडियाका भी सहयोग मिल रहा है, इससे वन विभाग के अधिकारी भी लोगों के सहयोग से वन प्रबंध व संरक्षण के कार्य को बढावा देने के लिए गाँवो में वन संरक्षण समितियों का गठन कर रहे हैं ।

कानूनी रूप से अभ्यारण्य क्षेत्रो में लोगो की भागीदारी से प्रबंध नही किया जा सकता है । इस व्यवस्था को देखते हुए भारतीय लोक प्रशासन संस्था, नई दिल्ली "सुरक्षित क्षेत्रो के प्रबंध में संयुक्त भागीदारी की संभावना" पर एक शोध कर रहा है । संस्था के अनुरोध पर कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य को भी इस शोध में शामिल किया गया है । संस्था इस शोध में पूर्ण भागीदारी कर रही है । इस शोध से आनेवाले परिणामों के बाद संस्था कार्य योजना निर्धारित कर इस विषय पर आगे भी कार्य करती रहेगी ।

अभ्यारण्य के बाहर के क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबन्ध के माध्यम से वनो के संरक्षण व विकासका कार्य वन विभाग के सहयोग से किया जायेगा ।

2. तालाब निर्माण

संस्था का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनो पर लोगों का नियंत्रण व प्रबन्ध होना चाहिए । अभ्यारण्य के अंदर बसे लखरुकी, गोंधरघुरा व दौलतिया गाँवों में पीने के पानीकी कमी की वजह से स्थानीय ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राज्य के अन्य हिस्सों को पलायन कर जाते रहे हैं । संस्था ने वर्ष की शुरूआत से ही सामुदायिक जल प्रबन्ध का ध्यान रखते हुए इन गाँवो के मध्य स्थित एक तालाब के पुनःनिर्माण व मरमत का लक्ष्य रखा । सरकारी अधिकारियों व राजनेताओं को वास्तविक स्थिती बताकर आर्थिक सहायता देनेका अनुरोध किया गया । अकाल राहत के तहत स्वीकृत इस तालाब के पुनःनिर्माण का कार्य वर्षा से पूर्व सम्पन हो जायेगा तब इस क्षेत्र में पानी की पर्याप्त पूर्ति हो जाने की संभावना है ।

इस क्षेत्र की पारिस्थिति देखते हुए इस क्षेत्र के पुराने तालाबों व पोखरों का पुनःनिर्माण, मरम्त तथा आवश्यक नये निर्माण कराये जाने की आवश्यकता स्थानीय ग्रामीण व संस्था महसूस करती है। संस्था सरकार के माध्यमसे अथवा अन्य साधन जुटाकर स्वयं इस कार्य को आगामी वर्षो में करने का विचार करती है ।

3. पीने के पानी की समस्या

अभ्यारण्य के अन्दर व इसकी सीमा पर बसे कई गाँवो में पीने के पानी की भारी समस्या रहती है। सरकार द्वारा लगवाये गये हैन्डपम्प पानी का स्तर नीचे उतर जाने की वजहसे कार्य करना बंद कर देते हैं तथा कुओं में पानी सुख जाता है । संस्था इस वर्ष प्रशासनको लगातार जानकारी देकर तथा मीडिया के माध्यमसे दबाय बनाकर लगभग 12 गाँवो में टेंकर के माध्यम से पीने का पानी गर्मीओं में उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी जिसके लिए प्रयास शुरू कर दिये गये हैं । संस्था आने वाले समय में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए देशज व वैज्ञानिक तथ्यों की जाँच करवा कर इस क्षेत्र में कार्य करेगी ।

4. पारिस्थितिकि विकास कार्यक्रम

संस्था कैलादेवी अभ्यारण्य के अन्तर्गत आनेवाली कैलादेवी ग्राम पंचायत के दो गाँवो व दस ढाणियों द्वारा अभ्यारण्य के उपर पड रहे दबाव को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकि विकास योजना तैयार कर रही है । यह योजना तैयार करने के लिए विश्व प्रकृति निधी–भारत की मदद मिल रही है । इस योजना को तैयार कर इसे सरकार सहित विभिन्न संस्थाओं को भेजा जायेगा ताकि कैलादेवी अभ्यारण्य के इन गाँवो को आदर्श के रूप में विकसित किया जा सके ।

5. बाघ परियोजना का पारिस्थितिकि विकास कार्यक्रम

भारत सरकार ग्लोबल इन्वायरनमेन्ट फेसिलिटी के सहयोग से रणथम्भोर सहित देश की सात बाघ परियोजनाओं में इन्डिया इकोडिवलपमेन्ट प्रोग्राम का क्रियान्वयन करने जा रही है । संस्था कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बाघ परियोजना प्रशासन को मदद करने जा रही है । संस्था की मदद पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम का सही तरीके से क्रियान्वयन तथा गाँवों के जबरदस्ती पुनःस्थापन नही होने देने के लिये है ।

6. अर्धशुष्क क्षेत्रों मे पर्यावरण शिक्षण

संस्था संसाधनो के प्रबन्ध में शिक्षण की आवश्यक्ता शुरु से ही महसुस करती आई है । राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों की बढती समस्याओं व उनके उचित हल के लिए प्रयास 1992 के भूमि सम्मेलन के बाद से तेजी से शुरू हुए हैं । इसे देखते हुए पर्यावरण शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, अहमदाबाद पश्चिमी पूर्वी भारत के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षण के नए कार्यक्रम शुरु करने जा रही है । सतत विकास संस्थान इस संस्था के साथ मिलकर पर्यावरण शिक्षण के अभिनव तरीकों का इस क्षेत्र में प्रयोग तथा कार्यो के कुछ आदर्श नमूने भी विकसित करेगी ।

7. जलग्रहण विकास कार्यक्रम

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष कर अर्धशुष्क क्षेत्रों का विकास जलग्रहण क्षेत्र विकास की दृष्टिसे करने के नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । संस्था जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर के आर्थिक सहयोग से करौली पंचायत समिति क्षेत्र में यह कार्यक्रम क्रियान्वित करने जा रही है । संस्था के चार कार्यकर्ता जल ग्रहण विकास दल के सदस्य के रूप में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण में जनवरी में भाग ले चुके हैं । प्रथम किस्त के जारी होते ही कार्य शुरु हो जायेगा । जल ग्रहण क्षेत्र में ग्रामीणो से प्रारंभिक सम्पर्क हो चुका है तथा ग्राम पंचायत ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है ।

8. निष्क्रमणकारी भेड समस्या

इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनो के विनाश में मारवाड से आने वाली निष्क्रमणकारी भेडों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है । पिछले 25 वर्षोसे आनेवाली इन भेडों की वजह से चारा व पेडों पर तो असर पडा ही है, स्थानीय निवासी भी इनके आते रहने से क्रोधित हैं और भेड पालकों व स्थानीय ग्रामीणो में तनाव रहने से झगडा होता रहता है । पिछले वर्षों में दोनो पक्षों के कई लोग हताहत भी हुए हैं । इन भेडों के इधर के वन क्षेत्र में चरने के लिए राज्य स्तर पर उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है, जिसमें पारिस्थितिकी नुक्सान का कोई ध्यान नही रखा जाता है ।

निष्क्रमणकारी भेडों की समस्या वर्षा के महिनों में होती है । इस समस्या को दूर करने के लिए संस्था स्थानीय वन अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं, ग्रामीणों के साथ मिलकर समस्या के प्रत्येक पहलू को समझने के साथ समाधान का प्रयास भी करेगी । आवश्यकता हुई तो निष्क्रमणकारी भेडों के आगमन को इस क्षेत्र में आने से रोकने के लिए अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा ।

9. ग्राम स्तरीय विकास संगठन निर्माण

संस्था विकास योजना से क्रियान्वयन तक के कार्यों के विकेन्द्रीकरण की हामी है । इसी सोच को लेकर संस्था अपने कार्यक्षेत्र के गाँवो में ग्राम विकास संगठनका निर्माण कार्य शुरु कर रही है । यही संगठन विकास की योजना तय करने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक का कार्य करेंगे, साथ ही साथ ग्राम सीमा (तन) में आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनो का प्रबन्ध भी करेंगे । इन संगठनो के निर्माण में गाँव में पूर्व से चले आ रहे अन्यान्य भेदों का ध्यान रखा जायेगा तथा कोशिश की जायेगी कि गाँव में इनके माध्यम से संगठन बन सके ।

10. पंचायती राज कार्यशाला

राजीव गाँधी फाऊन्डेशन, नई दिल्ली के सहयोग से पंचायती राज के विषय में कार्य करने वाली संस्थाओं, पंचायती राज कार्यकारियों तथा सरकारी अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन फरवरी में किया जाना था । परन्तु कुछ कारणोंवश यह कार्यशाला आयोजित नही हो सकी । इस कार्यशाला के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओ की मजबूती तथा उनके कार्यो में आने वाली बाधाओं को समझकर दूर करने के प्रयास किये जायेंगे । यह कार्यशाला अगले वर्ष में आयोजित की जायेगी।

11. पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती

संस्था मानती है कि पंचायतें विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं । राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओ की स्थिती व उनके क्षमता वर्धन के लिए संस्था द्वारा प्रयास किया जा रहा है । संस्था अन्य संस्थाओ के साथ मिलकर करौली व सपोटरा पंचायत समिति की 10 ग्राम पंचायतो के साथ मिल कर उनके क्षमता वर्धन के लिए आवश्यक प्रयास करेगी । इसके लिए उन्नति, अहमदाबाद से सहयोग लिया जा रहा है ।

12. खान मजदूर सुरक्षा

संस्था के कार्यक्षेत्र में सैण्ड स्टोन की खाने भारी मात्रा मे हैं, और हजारो ग्रामीण इन खानों मे मजदूरी पाते हैं । इन खान मजदूरों की स्थिति बन्धुआ मजदूरों जैसी है, और इनकी सुरक्षा व फायदे के लिए बनाये कानून यहां नही के बराबर लागू होते हैं । इसे देखते हुए संस्था ने इन मजदूरों के साथ कार्य करना तय किया है । शुरू में संस्था इस विषय मे अपनी क्षमता बढायेगी और उसके बाद ही संचार व सूचना के माध्यमसे सीधे कार्य मजदूरो के साथ शुरु किये जायेंगे ।

13. ढांचागत समायोजन का प्रभाव

संस्था 1991से जारी ढांचागत समायोजन व आर्थिक नीति के ग्रामीण समुदायों पर पढने वाले प्रभावों को जांचने के लिये एक सर्वे कार्य शुरु करने जा रही है । यह सर्वे कार्य आस्था, उदयपुर के सौजन्य से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है । इस सर्वे से पता लग सकेगा कि विभिन्न क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पडा है । यह सर्वेक्षण अगले वर्ष से शुरू होगा ।

कार्यशालाओं, बैठको व प्रशिक्षणमें शामिल संस्था के कार्यकर्ता

1. उन्नति, अहमदाबाद द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता वर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला 24–26, अप्रेल 1995
2. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति पर आयोजित बैठक 2, जून 1995
3. संयुक्त सहायता केन्द्र, गुडगाँव द्वारा आपदा प्रबन्ध पर आयोजित बैठक 11–13, जून 1995
4. भारतीय पर्यावरण समिति, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय अंकेक्षण, प्राकृतिक संसाधनो के प्रबंध तथा कचरा सूक्ष्मीकरण पर आयोजित कार्यशाला 14–18, जून 1995
5. आस्था, उदयपुर द्वारा विस्थापन व पुनर्वास नीति पर आयोजित कार्यशाला 22–23, जून 1995
6. आस्था, उदयपुर द्वारा नई आर्थिक नीति पर आयोजित कार्यशाला 28–30, जून 1995
7. आस्था, उदयपुर द्वारा नया वन विधेयक पर आयोजित कार्यशाला 5–6, जुलाई 1995
8. खान मजदूर सुरक्षा अभियान, जोधपुर द्वारा खान मजदूरों की स्थिति पर आयोजित कार्यशाला 7, जूलाई 1995
9. खान मजदूर सुरक्षा अभियान, जोधपुर द्वारा खान मजदूरों की स्थिति पर आयोजित कार्यशाला 8, जूलाई 1995
10. भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नया वन विधेयक पर वरोरा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला 13–16, जुलाई 1995
11. भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विस्थापन व पुनर्वास नीति पर वरोंरा मे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला 17–20, जुलाई 1995
12. बाल मजदूरों के लिए सम्बन्ध केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा बच्चे और पर्यावरण पर आयोजित कार्यशाला 4–6, अगस्त 1995
13. माईन्ड, नई दिल्ली द्वारा माईन्ड फेलोज की जमशेदपूर में आयोजित बैठक 22–23, अगस्त 1995
14. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर आयोजित बैठक 12, सितम्बर 1995
15. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर आयोजित बैठक 8, अक्तूबर 1995
16. खानमदूर सुरक्षा अभियान, जोधपुर द्वारा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला 28–29, अक्तूबर 1995
17. आस्था, उदयपुर द्वारा ढाँचागत समायोजन का प्रभाव पर आयोजित बैठक 5, दिसम्बर 1995
18. विश्व प्रकृति निधी–भारत, नई दिल्ली द्वारा NGO मोनीटरिंग कार्यशाला 7–8, दिसम्बर 1995
19. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रायोजित जलग्रहण विकास दल के चार सदस्यो का भारतीय ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षण 2–25, जनवरी 1996
20. रिसोर्स एन्ड सपोर्ट सेन्टर, बम्बई द्वारा राजस्थान विकास में स्वैच्छिक संगठनो के समनवय से भावी कार्यक्रम पर आयोजित बैठक 27, जनवरी 1996
21. माईन्ड, नई दिल्ली द्वारा माईन्ड फेलोज की मथुपुर में आयोजित बैठक 14–19, फरवरी 1996
22. आस्था, उदयपुर द्वारा ढाँचागत समायोजन का प्रभाव अध्ययन के लिए आयोजित प्रशिक्षण 23–24, फरवरी 1996

23. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर आयोजित बैठक 7, मार्च 1996
24. उन्नति, अहमदाबाद द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के क्षमतावर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला 15–16, मार्च 1996

संस्था के कार्य को देखने आने वाले व्यक्ति व संस्था

1. भारतीय लोक प्रशासन संस्था, नई दिल्ली से आशीष कोठारी व उनके सहयोगी संयुक्त सुरक्षित क्षेत्र प्रबन्ध के सम्बन्ध में । कु. प्रिया दास शोध कार्य हेतु ।
2. विज्ञान व पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली से नीना सिंह कैलादेवी वन्यजीवी अभ्यारण्य में सामुदायक वन प्रबन्ध को देखने ।
3. पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, अहमदाबाद से किरण देसाई व दिलीप सुरकर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षण के सम्बध में ।
4. तरुण भारत संघ, भीकमपुरा–किशोरी जिला अलवर के सचिव राजेन्द्रसिंह क्षेत्र में जल प्रबन्ध की संभावनाओ को देखने ।
5. नई दिल्ली से आउटलूक (अंग्रेजी) पत्रिका की संम्याददाता व फोटो ग्राफर कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य में लोगों द्वारा बचाये जा रहे जंगल विषय पर रिर्पोटिंग करने ।
6. मीपा क्रियेटर, मद्रास से राजस्थान में पंचायती राज विषय पर विडियो फिल्म बनाने के लिए।
7. उन्नति, अहमदाबाद से पंचायती राज संस्थाओ के क्षमता वर्धन के सम्बन्ध में ।

संस्था के अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध

1. विश्व प्रकृति निधी–भारत नई दिल्ली के एनजीओ मोनीटरींग नेटवर्क के सदस्य ।
2. टाईगर लिंक नई दिल्ली के सदस्य ।
3. आपदा प्रबन्धन में गैर सरकारी संस्था के आंतरराष्ट्रीय मंच नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य।
4. सामुदायिक जमीन संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति, धारवाड के सदस्य ।
5. खान मजदूर सुरक्षा अभियान, जोधपुर के सदस्य ।
6. उन्नति, अहमदाबाद की पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता वर्धन कार्यक्रम समूह के सदस्य ।
7. आस्था, उदयपुर के ढाँचागत समायोजन के प्रभाव कार्यक्रम समूह के सदस्य ।
8. चाईल्ड लेबर एक्शन नेटवर्क, नई दिल्ली के सदस्य ।